

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 806

जिसका उत्तर मंगलवार, 01 मार्च, 2015 को दिया जाना है

घाटे वाली सीपीएसई इकाइयों का बंद होना

806. श्री एस आर विजय कुमार:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री गजानन कीर्तिकर:
डॉ जे जयवर्धन:
श्री विद्युत वरण महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
डॉ सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नियमित रूप से लाभ उठा रहे केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के नाम क्या हैं;
- (ख) क्या सरकार ने नियमित रूप से घाटे में चल रहे केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) को विनिवेशित या बंद करने का निर्णय लिया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;
- (घ) क्या सरकार ने हाल ही में बंद हुई एचएमटी की अव्यवहार्य इकाइयों को बंद करने के लिए कोई वित्तीय सहायता/पैकेज प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने एचएमटी सहित ऐसे सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) भी स्वीकृत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क): भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि उठा रहे हैं:

- i. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड;
- ii. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड;
- iii. हिन्दुस्तान पेपर लिमिटेड;
- iv. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड;
- v. एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड;

- vi. एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड;
- vii. एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड;
- viii. एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड;
- ix. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड - इलेक्ट्रिकल मशीनरीज लिमिटेड;
- x. भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड;
- xi. इंडस्ट्रियल एंजिनरिंग लिमिटेड;
- xii. नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड;
- xiii. रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड;
- xiv. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड;
- xv. तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड;
- xvi. टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;

उपर्युक्त उद्यमों के अलावा पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2014-15 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों ने भी हानि उठाई है:

- i. एचएमटी लिमिटेड;
- ii. नेपा लिमिटेड;
- iii. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड;

(ख) से (ड): विनिवेश विभाग ने सूचित किया है कि उसने भारी उद्योग विभाग के अधीन हानि उठा रहे किसी भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के विनिवेश के लिए वर्तमान में किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

तथापि, भारी उद्योग विभाग पुनरुद्धार की संभावनाओं को आंकने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हानि उठा रहे प्रत्येक उद्यम की समीक्षा कर रहा है। इस कार्य के एक भाग के रूप में, हानि उठा रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनका कार्यापलट किए जाने की क्षमता है, उनका पुनरुद्धार किया जाता है और जो चिरकाल से रुग्ण हैं, उनके कर्मचारियों को देय प्रतिपूर्ति के भुगतान के पश्चात् कंपनी को विनिवेश या बंद किया जाता है।

तदनुसार, चिरकाल से रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों नामतः तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल), एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड, एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 6 जनवरी, 2015 को हुई अपनी बैठक में एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड को इसके कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश तथा सरकारी नीति के अनुसार चल और अचल संपत्तियों के निपटान करके बंद करने का अनुमोदन दे दिया है।

एचएमटी की तीन सहायक कंपनियों अर्थात् एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड को बंद करने के निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु कुल ₹427.48 करोड़ की नकद सहायता की आवश्यकता है। सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, एचएमटी की तीन सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए, 2007 वेतनमान पर आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज तथा 2007 नोशनल वेतनमानों पर ही उपदान और छुट्टी नकदीकरण की पेशकश की जाएगी।
